बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 39 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 18 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

एनआईए की कस्टडी में भेजा आमिर राशिद अली, 10 दिन होगी पूछताछ; खुल सकते हैं बड़े राज

नई दिल्ली । दिल्ली कार ब्लास्ट की साजिश रचने वाले आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे कस्टडी में भेज दिया गया। बता दें कि कल रविवार को एनआईए की टीम ने आतंकी उमर नबी के साथी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला था कि आमिर और उमर ने मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी। वहीं, आरोपी आमिर राशिद अली एनआईए की पूछताछ में बड़े खुलासे कर सकता है। अब एनआईए की टीम 10 दिन तक उससे पूछताछ करेगी। एनआईए की टीम ने कश्मीर के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है।

धमाके की चपेट में आए एक और व्यक्ति की मौत, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम

नई दिल्ली ।

लाल किला इलाके में हुए विस्फोट की घटना में एक और व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय विनय पाठक के रूप में हुई है। इस दुखद घटना के बाद विस्फोट में मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 14 हो गई है। विनय पाठक, जो बिहार के सीतामढ़ी के मूल निवासी थे। लाजपत राय मार्केट में सीसीटीवी कैमरे का सामान लेने आए थे।

एनएलजेपी में एक और घायल की मौत हुई, मृतकों की संख्या 13 पहुंची

लाल किला के पास बीते सोमवार को हुए बम धमाके में घायल जम्मू कश्मीर निवासी बिलाल पुत्र गुलाम अहमद की बृहस्पतिवार सुबह एलएनजेपी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल से बृहस्पतिवार सुबह बिलाल की मौत के बारे में सूचना मिली। 13 नंवबर को बिलाल की मौत के साथ दिल्ली बम ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। 28 घायलों का उपचार चल रहा था।

लालकिले बम धमाके की जांच एएनआई को

लाल किला बम धमाके की तीव्रता इतनी थी कि ब्लास्ट के बाद एक दुकान की छत पर बृहस्पतिवार सुबह एक कटा हुआ हाथ मिला। उत्तरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार कटा हुआ यह हाथ विस्फोट स्थल से कुछ मीटर दूर जैन मंदिर के पीछे मिला। पीड़ित की पहचान सुनिश्चित

करने के लिए कटे हुए हाथ को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।

सीसीटीवी फुटेज में उमर धमाके से पहले मस्जिद जाते हुए दिखा

दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें उस दिन मुख्य संदिग्ध डॉ. उमर नबी को बदरपुर बॉर्डर टोल प्लाजा से दिल्ली में प्रवेश करते हुए और बाद में रामलीला मैदान के नजदीक एक मस्जिद के पास टहलते हुए देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बदरपुर टोल प्लाजा के फुटेज में उमर को विस्फोट के दिन 10 नवंबर को एक सफेद हुंडई आई- 20 कार चलाते हुए और सुबह 8.02 बजे टोल गेट पर रुकते हुए देखा जा सकता है। कार कुछ देर के लिए रुकती है व उमर नकदी निकालता है और आगे बढ़ने से पहले उसे टोल ऑपरेटर को सौंप देता है।

एजेंसियों के पीछे लगने का पता था

पुलिस अधिकारी ने कहा कि मास्क पहने हुए उमर बार-बार सीसीटीवी कैमरे की ओर देख रहा था। संभवत- उसे पता था कि सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में हैं। यही वजह है वह सचेत होकर अपने आस-पास की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उसी दिन रामलीला मैदान के पास एक मस्जिद के पास की गली से एक और सीसीटीवी क्लिप में उमर एक संकरी सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है। वह कुछ देर के लिए अपना सिर घुमाता है तो उसका चेहरा कैमरे में दर्ज हो जाता है। पुलिस को संदेह है कि लाल किला की ओर बढ़ने से पहले वह नमाज अदा करने मस्जिद गया था।

पुलिस ने कहा कि उमर नबी के संभावित संचालकों का पता लगाने तथा उसकी दिनभर की गतिविधियों की जानकारी जुटाने का प्रयास जारी हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसका कोई साथी था। जांच में ये बात सामने आई है कि सफेदपोश जैश का ये मोड्यूल देशभर में 32 कारों से धमाके की साजिश थी, दिल्ली कार ब्लास्ट इसी का हिस्सा था।

बिहार नतीजों पर राहुल के बाद रॉबर्ट वाड्रा का भी हमला: कहा- परिणाम आश्चर्यजनक, लोकतंत्र बचाना ही लक्ष्य

नई दिल्ली । भारतीय उद्यमी रॉबर्ट वाड्रा ने विजयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो सरकार अभी बनी है, उसे अपने किए वादों को पूरा करना होगा। राहुल कल वहाँ लोगों के बीच होंगे। कई युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, और यह अपने आप में एक आंदोलन होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है। इसके अलावा, उन्होंने देश में लोकतंत्र बचाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा कि लोग नतीजों से खुश नहीं हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका कड़ी मेहनत करते रहेंगे, और हमें देश भर में लोकतंत्र बचाना है; यही सबसे ज़रूरी है। यह लड़ाई जारी रहेगी, और सभी को लगता है कि यह देश के लिए हानिकारक है। निष्पक्ष चुनाव के बिना कोई प्रगति नहीं होगी। यही सबकी सोच है। शुक्रवार को, कांग्रेस

नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव शुरू से ही अनुचित था, क्योंकि पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद दहाई अंक तक नहीं पहुँच पाई। गांधी ने कहा कि पार्टी चुनाव के बाद अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और आश्वासन दिया कि कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। ङ्क पर एक पोस्ट में, राहुल गांधी ने कहा, मैं बिहार के उन लाखों मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने महागठबंधन में अपना विश्वास व्यक्त किया। बिहार में यह परिणाम वाकई आश्चर्यजनक है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही अनुचित था। उन्होंने आगे कहा कि यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। कांग्रेस पार्टी और भारत गठबंधन इस परिणाम की गहन समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और भी प्रभावी बनाएंगे। इस बीच, सत्तारूढ़ एनडीए को 202 सीटें मिलीं, जो 243 सदस्यीय सदन में तीन-चौथाई बहुमत है। यह दूसरी बार है जब एनडीए ने विधानसभा चुनावों में 200 का आंकड़ा पार किया है। 2010 के चुनावों में, इसने 206 सीटें जीती थीं। महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिलीं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 25 सीटें, कांग्रेस ने 6, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) - सीपीआई (एमएल) (एल) - दो, भारतीय समावेशी पार्टी (आईआईपी) - एक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) - सीपीआई (एम) एक सीट पर जीत हासिल की। जबकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने पांच सीटें और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को एक सीट मिली।

दिल्ली पुलिस ने पकड़ा कुख्यात साइकिल चोर! 16 चोरी की साइकिलें बराम

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की द्वारका दक्षिण थाना टीम ने एक बड़े सफल अभियान में कुख्यात साइकिल चोर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 16 चोरी की साइकिल बरामद की गई, जिससे क्षेत्र में हुई चोरी की छह घटनाओं का खुलासा हुआ.मामले की शुरुआत द्वारका दक्षिण क्षेत्र में साइकिल चोरी की बढ़ती शिकायतों से हुई, जहां कई लोगों ने साइकिल चोरी की शिकायत की. एसीपी द्वारका किशोर कुमार रेवाला के पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर राजेश कुमार साह (एसएचओ, द्वारका दक्षिण) ने एक विशेष टीम गठित की. टीम में हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार (987/डीडब्ल्यू), मनोज कुमार (828/डीडब्ल्यू), गजे सिंह (1030/डीडब्ल्यू), सुरेंद्र (764/डीडब्ल्यू) और कांस्टेबल तुषार यादव (1803/डीडब्ल्यू) शामिल थे. टीम ने आसपास के इलाकों में लगे 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया गया और तकनीकी व मैनुअल खुफिया जानकारी एकत्र की गई. 28 अक्टूबर 2025 को शाम करीब 7 बजे हेड कांस्टेबल मनोज कुमार को गुप्त सूचना मिली कि चोर कुछ ही मिनटों में डीडीए पार्क या भैंस वाला पार्क के पास आएगा. टीम ने तुरंत भैंस वाला पार्क के पास घेराबंदी की. कुछ देर बाद गणपति चौक की ओर से एक व्यक्ति साइकिल चलाते हुए आता दिखा. वह संदिग्ध लगा. पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी साइकिल छोड़कर सेक्टर 7 के डीडीए पार्क की ओर भागने लगा. पुलिस ने पीछा किया और उसे दबोच लिया.शुरुआती जांच में पता चला कि साइकिल ई-एफआईआर 80101951/2025 (धारा 303(2) बीएनएस, थाना द्वारका दक्षिण) के तहत चोरी की थी. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने यह साइकिल रामफल चौक रोड, इंस्टाइल सैलून, सेक्टर 7 के सामने से चुराई थी. आगे की पूछताछ में उसने अन्य चोरियों की बात स्वीकारी. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से 15 और साइकिल बरामद कीं. अब तक कुल 16 साइकिल बरामद हुई है.

अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक; दिल्ली विस्फोट पीड़ितों को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली । सोमवार को फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक एक गंभीर माहौल में शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ 10 नवंबर को दिल्ली में हुए कार बम विस्फोट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के उपराज्यपाल और प्रशासक भी शामिल हुए। केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। परिषद केंद्र और सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मुद्दों और विवादों के समाधान और प्रगति के लिए एक मंच प्रदान करती है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे शामिल हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जाँच और उनके त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का कार्यान्वयन शामिल है। बैठक में प्रत्येक गाँव के निर्दिष्ट क्षेत्रों में भौतिक बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) को लागू करने और पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली को मजबूत करने सहित विभिन्न क्षेत्रीय स्तर के साझा हित के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। शाह परिषद के अध्यक्ष हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। यह बैठक गृह मंत्रालय के अंतर-रायीय परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसकी मेज़बानी हरियाणा सरकार कर रही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के अंतर्गत, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद सहित पाँच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। एक सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री (प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से) उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक सदस्य राज्य से, राज्यपाल दो मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित करते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिव स्तर की एक स्थायी समिति भी गठित की है। राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को प्रारंभ में संबंधित क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। स्थायी समिति द्वारा विचार-विमर्श के बाद, शेष मुद्दों को आगे विचार-विमर्श के लिए क्षेत्रीय परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। इस विश्वास के साथ कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, क्षेत्रीय परिषदें दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर संवाद और चर्चा के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करती हैं और इसके माध्यम से आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती हैं।

बीआरएस विधायकों की अयोग्यता का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को भेजा अवमानना नोटिस

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीआरएस विधायकों के अयोग्यता मामले पर तेलंगाना के स्पीकर को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस, विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के निर्देश का पालन न करने के लिए जारी किया। बीती 31 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिया था कि वे तीन महीने के भीतर बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लें। हालांकि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद तय समयसीमा के भीतर फैसला नहीं लिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान पीठ ने इसे अदालत की घोर अवमानना माना और स्पीकर को नोटिस जारी किया है। हालांकि पीठ ने तेलंगाना स्पीकर को अभी अगले

आदेश तक अदालत में पेश होने से छूट दे दी है। तेलंगाना विधानसभा स्पीकर कार्यालय की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए आठ हफ्तों का समय और देने की मांग की गई है।

इस याचिका पर भी अदालत ने नोटिस जारी किया है। स्पीकर ऑफिस की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि विधायकों की अयोग्यता संबंधी चार मामलों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और तीन अन्य में सबूत रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इस पर सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। यह अदालत की घोर अवमानना है। अब ये वो ही फैसला करें कि क्या वे नए साल का जश्न मनाना चाहते हैं। अदालत ने फिलहाल मामले की सुनवाई चार हफ्तों के लिए टाल दी है। जिन विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होना है, वे बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दल-बदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर को विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो बीआरएस नेता केटी रामाराव, पदी कौशिक रेड्डी और केओ विवेकानंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जिसके बाद बीती 31 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिया था कि वे तीन महीने के भीतर बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लें।

रोग केवल शरीर को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं

वैश्विक स्तरपर आधुनिक मानव सभ्यता आज जिस डिजिटल और प्रौद्योगिकीय उन्नति के शिखर पर खड़ी है, उसे देखते हुए यह मानना स्वाभाविक लगता है कि विज्ञान की शक्ति ने दुनियाँ को लगभग हर समस्या का समाधान देना शुरू कर दिया होगा।कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स क्वांटम कंप्यूटिंग और जेनेटिक एडिटिंग जैसी तकनीकों ने हमारे जीवन को जितना सरल बनाया है, उतनी ही आशाएं भी जगाई हैं। किंतु, विरोधाभास यह है कि इस टेक्नोलॉजी-प्रधान सामयिक दुनियाँ में भी पृथ्वी के प्रत्येक देश को अनेक प्रकार की बीमारियाँ चुनौती के रूप में घेरे हुए है। अनेक रोग ऐसे है जिनके उपचार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है,परंतु अब भी कई बीमारियाँ मनुष्य और चिकित्सा जगत के लिए पहेली समान बनी हुई है। यह परिदृश्य न केवल चिकित्सा प्रणाली की निरंतर विकसित होने का संदेश देती है,बल्कि यह भी दर्शाती है कि रोगों के विरुद्ध अंतिम जीत अभी दूर है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि दुनियाँ भर में आज भी लाखों लोग उन बीमारियों में संघर्ष कर रहे हैं,जो या तो लाइलाज हैं या जिनका उपचार कठिन, महंगा और अत्यंत जटिल है। ऐसे रोग केवल शरीर को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव डालते है। कैंसर इसका प्रमुख उदाहरण है,एक ऐसी बीमारी जिसकी तीव्रता और विस्फोटक विस्तार आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए आज भी अत्यंत बड़ी चुनौती बना हुआ है। कैंसर के अनेक प्रकार,उनकी विविधतापूर्ण प्रकृति और तेजी से फैलने वाले स्वरूप ने यह सिद्ध कर दिया है कि रोगों से लड़ाई विज्ञान और समाज दोनों स्तरों पर बराबर की लड़ाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में कैंसर के मामलों में असाधारण वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाती है कि आधुनिक जीवनशैली और पर्यावरणीय परिवर्तन भी इस रोग के कारकों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम बीमारियों पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी संदर्भ में, 17 नवंबर 2025 को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय मिर्गी दिवस(नेशनल एपिलेप्सी डे) अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है।मिर्गी (एपिलेप्सी) एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल विकार है जो विश्व की लगभग 5 करोड़ आबादी को प्रभावित करता है, और यह आंकड़ा इसे दुनियाँ के सर्वाधिक सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकारों में शामिल करता है। इस विकार से पीड़ित लोगों को सामाजिक भेदभाव, गलत धारणाओं और असमंजस का सामना करना पड़ता है। बता दें समस्या पहले यह माना जाता है की यह एक संक्रामक बीमारी है जिस कारण मरीज की कोई सहायता करने से भी डरता है लेकिन यह एक असंक्रामक बीमारी है और हमारे अंदर नहीं फैल सकती है। दूसरी अफवाह यह है की अगर किसी को दौरे पड़ रहे हैं तो उसे भूत प्रेत और जादू टोने से जोड़ दिया जाता है जो पूरी तरह से झूठ है।मिर्गी के मरीज को जूता सुंघाना, उसके मुंह में चम्मच डालना भी आधार रहित बातें हैं,ऐसे में जागरूकता, स्वीकार्यता और वैज्ञानिक जानकारी ही वह हथियार है जो मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बेहतर, सुरक्षित और सम्मानजनक बना सकता है। साथियों बात अगर हम राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के मुख्य उद्देश्य को समझने की करें तो, लोगों को यह समझाना है कि मिर्गी कोई अलौकिक घटना नहीं, बल्कि मस्तिष्क का चिकित्सकीय विकार है; इसका इलाज मौजूद है; और सही देखभाल तथा जागरूकता से व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। इस दिवस पर चिकित्सा जगत, समाज और सरकारें मिलकर एक संगठित अभियान के माध्यम से मिर्गी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करती हैं। यह संदेश दुनिया के हर देश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि बीमारियाँ और विकारों का मानव जीवन पर प्रभाव सीमाओं को पार कर वैश्विक स्वरूप धारण करता है। साथियों बात अगर हम जीवनशैली में परिवर्तन, रोग को बढ़ावा देने वाले कारकों से बचाव को समझने की करें तो रोगों के उपचार में केवल दवाइयाँ और चिकित्सा हस्तक्षेप ही पर्याप्त नहीं होते;जीवनशैली में परिवर्तन रोग को बढ़ावा देने वाले कारकों से बचाव, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान तथा नियमित दिनचर्या स्वास्थ्य को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। कई बीमारियाँ ऐसी होती है जिनका प्रमुख कारण अनुचित जीवनशैली, असंतुलित आहार, तनाव, पर्यावरणीय प्रदूषण और गतिहीन दिनचर्या होती है। विशेषज्ञ में अध्ययन यह दर्शाते हैं कि एक बड़ी संख्या उन रोगों की है जिनका प्रतिशत केवल जीवनशैली सुधार, जैसे स्वस्थ भोजन,नियमित व्यायाम,पर्याप्त नींद,मानसिक संतुलन औरतनाव प्रबंधन से कम किया जा सकता है। मिर्गी के संदर्भ में भी यह पूर्णतः सत्य है। मिर्गी का दौरा कई बार नींद की कमी, तेज़ रोशनी, दिमागी तनाव, शराब सेवन या दवाई छोड़ देने से ट्रिगर हो जाता है। इसलिए, रोग की समझ और जीवनशैली का अनुशासन व्यक्ति को सुरक्षित रखने का सबसे विश्वसनीय तरीका है। जीवनशैली सुधार के अतिरिक्त, जागरूकता वह सटीक और शक्तिशाली अस्त्र है जो रोगों की रोकथाम, उपचार और प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। दुनिया के अनेक देशों में स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता अभियानों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। पोलियो, एड्स, क्षयरोग और कोविड-19 जैसी बड़ी महामारियों के दौरान भी जागरूकता ने निर्णायक भूमिका निभाई। रोग को समझना, लक्षणों को पहचानना, उपचार को जानना और गलत धारणाओं से दूर रहना,ये सभी बातें व्यक्ति को बीमारी से बचाने में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आधुनिक दवाइयाँ और तकनीकें। साथियों बात अगर हम आज डिजिटल मीडिया, इंटरनेट और शिक्षा के विस्तार के कारण स्वास्थ्य से संबंधित लाभ हानि को समझने की करें तो,जानकारी पहले की तुलना में कहीं अधिक सुलभ हो गई है। किंतु इसके साथ ही गलत सूचनाओं का प्रसार भी उतनी ही तेजी से हुआ है। ऐसे में वास्तविक,वैज्ञानिक और सत्य आधारित जानकारी लोगों तक पहुँचना बेहद आवश्यक हो गया है। मिर्गी जैसे विकारों को लेकर अभी भी विभिन्न देशों में मिथक और अंधविश्वास फैले हुए हैं। कुछ लोग इसे दैवी या अलौकिक घटना समझते है, कुछ इसे मानसिक कमजोरी से जोड़ते हैं और कुछ इसे सामाजिक कलंक की तरह देखते हैं। इस सोच को बदलने का एकमात्र तरीका है, जागरूकता, संवाद और सटीक सूचना का प्रसार। साथियों बात अगर हम विश्व के कई देशों में ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसको समझने की करें तो उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में समान अवसर नहीं मिल पाते। यह स्थिति न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक विकास में भी बड़ी बाधा बनती है। इसलिए, विकारों को त्यागने का संदेश और सामाजिक स्वीकार्यता आज के स्वास्थ्य विमर्श के अत्यंत आवश्यक हिस्सा है। मिर्गी, कैंसर या किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सहानुभूति, सम्मान और सहयोग की आवश्यकता होती है,न कि भेदभाव, दूरी या भय की। यदि सामाजिक रूप से स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो, तो बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति पुनर्वास और सुधार की दिशा में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकता है।यह भी स्वीकार करना होगा कि स्वास्थ्य केवलचिकित्सा प्रणाली का विषय नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक संरचना का हिस्सा है। बीमारियों से लड़ाई तभी सफल हो सकती है जब सरकारें, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सामाजिक संस्थाएँ, स्कूल, मीडिया और आम नागरिक मिलकर एक वैश्विक प्रयास करें। इस संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, रेड क्रॉस जैसी संस्थाएँ दुनिया के विभिन्न देशों में बीमारियों के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में निरंतर कार्यरत हैं। साथियों बात अगर हम इस तथ्य को समझने की करें कि आज की दुनियाँ में यह आवश्यक है कि हम बीमारी को केवल चिकित्सा दृष्टि से नहीं,बल्कि एक समग्र सामाजिक -मानवीय दृष्टि से देखें। रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या तब ही कम होगी जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति में जागरूकता का विस्तार होगा, जीवनशैली में सुधार आएगा और बीमारियों के विरुद्ध सामूहिक प्रयास होंगे। हमें यह समझना होगा कि कोई भी रोग किसी एक व्यक्ति, परिवार या देश की समस्या नहीं है; यह संपूर्ण मानवता की साझा चुनौती है।इसलिए, 17 नवंबर 2025 का राष्ट्रीय मिर्गी दिवस केवल भारत का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक वैश्विक संदेश है,कि बीमारियों और विकारों से लड़ाई में जागरूकता, सहानुभूति, विज्ञान और उचित जीवनशैली के माध्यम से ही सफलता पाई जा सकती है। यह दिन न केवल मिर्गी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है, बल्कि आधुनिक दुनिया को यह याद दिलाने का भी मंच है कि जब तक मानवता के किसी भी हिस्से में कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, तब तक हमारी जिम्मेदारी नहीं होती।

सम्पादकीय...

परमाणु जखीरा

अंततः डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका ने 33 वर्ष बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू कर दिया। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के तहत आने वाली सैंडिया नेशनल लैबोरेट्रीज ने अपने आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका ने बी-61-12 टैक्टिकल थर्मो न्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण 19 से 21 अगस्त के बीच नेवादा टेस्ट साइट पर किया गया जिसमें अत्याधुनिक एफ-35ए स्टैल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, एफ-35ए ने परीक्षण के दौरान बी-61-12 के इनर्ट वर्जन को सुरक्षित दिशा-निर्देशों के बीच उड़ाया और तय लक्ष्य पर सटीकता से गिराया। यह परीक्षण अभ्यास एनएनएसए के साथ मिलकर किया गया था। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि पहली बार थर्मल प्रीकंडीशनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब कि बम के जॉइंट टेस्ट असेंबली को अत्यधिक तापमान बदलावों से गुजारा गया ताकि यह पता चल सके कि असल युद्ध की कठिन परिस्थितियों में यह हथियार कितना सक्षम रहेगा। एफ-35 के साथ ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था।ट्रंप ने जब परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया था तब दुनिया सोच रही थी कि क्या वास्तव में ट्रंप ऐसा करेंगे या वह सिर्फ रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया पर दबाव बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब अमेरिका ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया को हिला दिया है। इससे रूस, चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका पूरी दुनिया में खुद को सबसे मजबूत दिखाना चाहता है। अमेरिका ने परमाणु परीक्षण कर अपनी परमाणु नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इससे दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ बढ़ेगी। रूस, चीन और अन्य देश भी अब परमाणु परीक्षण फिर से शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और ईरान अपने हथियार भंडार का विस्तार करने के लिए परीक्षण कर सकते हैं। इससे वैश्विक अस्थिरता और बढ़ जाएगी। अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया था। भौतिकी वैज्ञानिक जे. रोबोट ओपेन हाइमर ने परमाणु परियोजना का नेतृत्व किया था और उनके साथ एनरिको फर्मी, रिचर्ड फेनमैन और नील्सबोर आदि वैज्ञानिक भी थे। परमाणु विस्फोट के बाद इसके भयानक परिणाम देखने के बाद ओपेन हाइमर ने हिन्दू धर्म ग्रंथ भगवद्गीता का प्रसिद्ध उदाहरण दिया और कहा अब मैं मृत्यु बन गया हूं संसार का संहार करने वाला'' इस परीक्षण के ठीक तीन हफ्ते बाद अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। इस हमले ने पलभर में विनाश कर डाला। लगभग 2 लाख लोग मारे गए। हजारों लोग अपंग हुए। कई वर्षों तक विकृत बच्चे जन्म लेते रहे और दोनों शहर खंडहर में तब्दील हो गए। इस हमले के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया लेकिन इसके बाद दुनियाभर में परमाणु हथियारों को लेकर एक दौड़ शुरू हो गई। आज दुनिया में इतने परमाणु बम हैं जिनसे दुनिया को कई बार बर्बाद किया जा सकता है। इसके बावजूद परमाणु ताकत हासिल करने की दौड़ खत्म नहीं हुई। दुनिया एक तरफ से परमाणु बमों के जखीरे पर बैठी है। इसका अर्थ यह है कि मानवता एक बहुत बड़े और आसन्न खतरे के मुहाने पर है। दुनिया के 9 देशों के सामूहिक विनाश के पर्याप्त हथियार हैं। इन हथियारों का उपयोग चाहे जानबूझ कर किया जाए या किसी दुर्घटना, साइबर हमले के कारण हो, दुनिया के बड़े हिस्से को तबाह कर सकता है। परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए कई संधियां हुईं। 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) हुई थी ताकि तनाव को कम किया जा सके। यह संधि अपने आप में भेदभावपूर्ण रही क्योंकि वैश्विक शक्तियों ने खुद को जिम्मेदार बताकर परमाणु परीक्षण करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखे लेकिन दूसरों को परमाणु परीक्षण करने से रोका। रूस ने सन् 2000 में इस पर हस्ताक्षर किए लेकिन वर्ष 2023 में इसे रद्द कर दिया। अमेरिका ने भी बाद में इसे रद्द कर दिया। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि को भेदभावपूर्ण बताते हुए हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत क्या करेगा। क्या वह फिर से परमाणु परीक्षण करेगा क्योंकि अगर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन परमाणु परीक्षण करते हैं तो भारत भी ऐसा करने को विवश होगा। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु परीक्षण पर अनिश्चितकालीन रोक लगाई थी। रोक को हटाना इस दुविधा का केवल एक हिस्सा है। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद क्लिंटन प्रशासन के तहत स्ट्रोब टैलबॉट और जसवंत सिंह के बीच परमाणु वार्ता हुई जो जॉर्ज. डब्ल्यू. बुश प्रशासन में भी चलती रही और जिसका नतीजा 2005 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के रूप में निकला। फिर भारत और अमेरिका के बीच 123 समझौते को लेकर बातचीत हुई और 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) ने स्पष्ट रूप से छूट दी जिससे परमाणु ईंधन, तकनीक और वाणिज्य तक भारत की पहुंच आसान हो गई। निश्चित रूप से 123 समझौते के तहत भारत के पास अतिरिक्त परीक्षण के लिए बेहद कम गुंजाइश है। हालांकि, अगर भारत को बेहद जरूरी हालात में ये कवायद आवश्यक लगती है तो एनएसजी (भारत के सभी परमाणु साझेदार छोड़ भी दें) भारत के द्वारा परमाणु परीक्षणों के नए दौर को 123 समझौते और एनएसजी छूट का उल्लंघन मान सकता है जिसके कारण नए सिरे से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके नतीजे बहुत गंभीर होने की संभावना है। अगर भारत परमाणु परीक्षण करता है तो उसे ट्रंप प्रशासन के मनमानेपन से भी जूझना होगा। भारत हमेशा शांति का पुजारी रहा है लेकिन उसे अपने सुरक्षा हितों को भी ध्यान में रखना होगा।

बिहार परिणाम : राजनीति का नया अध्याय

इस बार बिहार एक नए उजाले और बिल्कुल नए आत्मविश्वास के साथ जागा है। चुनावी नतीजों के शुरुआती रुझानों के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि जनता ने इस बार केवल वोट नहीं डाला, अपनी राजनीति की दिशा खुद तय की है। क्योंकि शुरुआती रुझानों से लेकर अंतिम तस्वीर तक, पूरा परिदृश्य एक ही संदेश दे रहा था कि बिहार अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) ने शायद खुद भी इतनी विशाल विजय की कल्पना नहीं की थी। 243 में से 207 सीटों का प्रचंड बहुमत एन.डी.ए. को मिलना! यह जीत केवल आंकड़ों की नहीं है। यह बिहार के मतदाता के बदले हुए राजनीतिक विवेक, उसकी परिपक्वता और उसकी नई प्राथमिकताओं की पहचान है। बिहार के लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब परिवारवाद अथवा भावनात्मक नारों का नहीं, परिणाम और भरोसे का रास्ता चुन चुके हैं। खास बात यह रही कि इस बार बिहार ने मतदान प्रतिशत में भी इतिहास रचा। 67 प्रतिशत का रिकॉर्ड मतदान और उसमें 71 प्रतिशत महिलाओं की धमाकेदार भागीदारी बताता है कि यह केवल चुनाव नहीं बल्कि समाज की गहराई में घट रही शांत क्रांति का उद्घोष था। गांवों और शहरों में महिलाएं बूथों पर ऐसे पहुंचीं जैसे वे अपने जीवन का नया अध्याय लिखने निकली हों। उनके वोट में योजनाओं का लाभ, सुरक्षा की अनुभूति और रोजमर्रा के जीवन में आए सुधारों का अनुभव था। पहली बार महिलाएं केवल वोटर नहीं, परिणाम की निर्णायक निर्माता बन कर उभरीं। इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण विषय यह रहा कि बदलते बिहार में नए राजनीतिक प्रयोगों के प्रति उत्सुकता तो दिखी लेकिन वह विश्वास में नहीं बदल सकी। इसे बिहार के मतदाता की दूर दृष्टि कहें या नीतीश-मोदी की जोड़ी पर उसका अटूट विश्वास कि दिल्ली में 'आप' की उल्लेखनीय सफलता के विपरीत, जन सुराज जैसे नवप्रयोग बिहार में अपना खाता तक खोलने में विफल रहे। कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई और तेजस्वी अपनी सीट बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। बिहार के मतदाता ने सब सुना, परखा, समझा पर अंत में उसी नेतृत्व पर भरोसा किया जो उन्हें स्थिरता और स्पष्टता के साथ बिहार को कानून व्यवस्था एवं प्रगति की राह पर ले जाता दिखाई दिया। स्पष्ट है कि बिहार का मतदाता अब सपनों से नहीं, सबूतों से प्रभावित होता है। वो खोखले वादों या सिद्धांतहीन बयानबाजी की राजनीति से तंग आ चुका है। यही कारण रहा कि 'वोट चोरी' जैसे आरोप भी जनता के बीच मुद्दा ही नहीं बन सके। मतदान का प्रतिशत बताता है कि लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास पहले से कहीं मजबूत दिखा और वास्तविक संघर्ष बूथ प्रबंधन तथा जमीनी संगठन क्षमता का रहा। जिसने बूथ संभाला, उसने चुनाव संभाला।

एन.डी.ए. इस मैदान में निर्णायक रूप से आगे रहा। निश्चित रूप से मोदी फैक्टर इस चुनाव में हमेशा की तरह मजबूत रहा। देश के जनमानस में यह भावना दृढ़ हो रही है कि विकास, स्थिरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व विश्वसनीय है। बिहार के मतपत्रों में भी इसी विश्वास की प्रतिध्वनि महसूस की गई। राज्य की स्थिरता और केंद्र की विश्वसनीयता, दोनों ने मिलकर इस जनादेश को आकार दिया। कांग्रेस का एक सीट पर सिमटना और तेजस्वी यादव का अपनी ही सीट पर संघर्ष करना, यह दृश्य सिर्फ राजनीतिक हार नहीं, एक बड़ा मनोवैज्ञानिक संकेत है कि लालू यादव की विरासत भावनात्मक तो है, पर अब निर्णायक नहीं। तेजस्वी की युवा ऊर्जा सीमित दायरे में रह गई और राहुल गांधी की अपील बिहार की जमीन में जड़ें नहीं जमा सकी। एन.डी.ए. की आंधी के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। न नैरेटिव में, न संगठन में, न ही नेतृत्व में। क्योंकि अतीत की स्मृतियां अब भी बिहार के मन में जीवित हैं। 'जंगल राज' शब्द सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि कई परिवारों के लिए वास्तविक पीड़ा रहा है। इसी कारण सुरक्षा, स्थिरता और शासन की निरंतरता इस बार प्रमुख मुद्दों के रूप में उभरे। इन नतीजों से जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे अनिश्चितता नहीं, व्यवस्था चाहिए। उसे अतीत नहीं, भविष्य चाहिए। युवा मतदाता भी इस चुनाव का मूक परिवर्तनकारी चेहरा रहा। उन्हें शिक्षा, कौशल, नौकरी और ऐसा राज्य चाहिए जहां से पलायन नहीं, रहने में गर्व हो। प्रवास की मजबूरियों के बीच भी, घरों में महिलाओं और युवाओं ने जिस गंभीरता से मतदान किया, उसने परिणाम की दिशा बदल दी। अंततः इस जनादेश की सबसे बड़ी जीत किसी दल या नेता की नहीं बल्कि बिहार के जागे हुए मतदाता की है। उसने दिखा दिया कि वह अब सोचकर, समझकर, तौलकर वोट देता है। वह किसी भ्रम में नहीं आता और किसी स्थायी नारे के पीछे नहीं चलता। बिहार ने अपना निर्णय दे दिया है। गहरा, स्पष्ट और संयत। अब बिहार इंतजार नहीं करता, बिहार अपेक्षा करता है। और यही अपेक्षा लोकतंत्र की सबसे सुंदर, सबसे सशक्त ध्वनि है।

आतंकवाद, प्रदूषण और सुरक्षा संबंधी चिंताओं से जूझती हमारी दिल्ली

भारत की राजधानी दिल्ली शक्ति, राजनीति और प्रगति का प्रतीक है। फिर भी, इसके चमकदार क्षितिज और राजनीतिक महत्व के पीछे एक कठोर वास्तविकता छिपी है। यहां आतंकवाद, प्रदूषण और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का बढ़ता खतरा है, खासकर उन बच्चों के लिए जो रोजाना स्कूल जाते हैं। लगातार हाई अलर्ट पर रहने वाले शहर में, दृश्य और अदृश्य दोनों तरह के खतरे अब दिल्लीवासियों के जीने और अपने परिवारों के पालन-पोषण के तरीके को आकार दे रहे हैं। हर सुबह, दिल्ली में लाखों स्कूली बच्चे ट्रैफि क जाम, धुंध और अनिश्चितता का सामना करते हुए बसों, ऑटो और कारों में सवार होते हैं। माता-पिता उत्सुकता से देखते हैं कि उनके बच्चे धुंध में कैसे गायब हो जाते हैं जो न केवल प्रतीकात्मक है बल्कि खतरनाक रूप से वास्तविक भी है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए.क्यू.आई.) अक्सर 'गंभीर' स्तर को छू जाता है, जिससे हवा जहरीली हो जाती है। दिल्ली में सांस लेना एक दिन में कई सिगरेट पीने के बराबर है। जहां प्रदूषण चुपचाप युवा फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं आतंकवाद का एक और साया मंडरा रहा है। दिल्ली ने पिछले कुछ वर्षों में कई आतंकवादी हमलों का सामना किया है- 2001 में संसद पर हमले से लेकर 2005 और 2008 में बाजारों और सार्वजनिक स्थलों को हिलाकर रख देने वाले विस्फोटों तक। 2025 में भी, अपने राजनीतिक महत्व के कारण यह शहर एक संभावित निशाना बना हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर रखती है लेकिन 'क्या होगा अगर' का डर दिल्लीवासियों के मन से कभी नहीं जाता। स्कूल, मॉल, मैट्रो स्टेशन और सार्वजनिक समारोहों पर लगातार नजर रखी जाती है। इन सबके बावजूद, ऐसे खतरों के बीच रहने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कम नहीं हो सकता। दिल्ली के स्कूली बच्चों के लिए, सुरक्षा ने एक नया अर्थ ग्रहण कर लिया है। सड़क सुरक्षा और अनुशासन के अलावा, माता-पिता और स्कूल अब आपातकालीन अभ्यास, निकासी योजनाओं और वायु शोधक मास्क पर भी चर्चा करते हैं। दिल्ली में पल रही एक पीढ़ी न केवल ए.बी.सी. और गिनती सीख रही है बल्कि अलार्म, सुरक्षा जांच और प्रदूषण मास्क से निपटना भी सीख रही है। लेकिन जहां प्रदूषण एक प्रत्यक्ष खतरा है, वहीं आतंकवाद एक अप्रत्याशित खतरा बना हुआ है। शहर के स्कूलों, खासकर सरकारी इमारतों या संवेदनशील क्षेत्रों के पास वाले स्कूलों में, कड़े सुरक्षा उपाय हैं जैसे सशस्त्र गार्ड, पहचान पत्र सत्यापन, सी.सी.टी.वी. नेटवर्क आदि। फि र भी डर बना रहता है। बच्चों के लिए ये सुरक्षा जांचें उनके सामान्य जीवन का हिस्सा बन गई हैं । दिल्ली के सुरक्षा बल खतरों को रोकने के लिए अथक प्रयास करते हैं लेकिन शहर की विशाल आबादी और छिद्रपूर्ण सीमाएं इस काम को जटिल बना देती हैं। हर दिन हजारों लोग शहर में आते-जाते हैं। बड़े समारोह, राजनीतिक रैलियां, त्यौहार, विरोध प्रदर्शन सुरक्षा व्यवस्था पर भारी पड़ते हैं। इसके अलावा प्रदूषण का संकट भी है। खासकर हर सर्दियों में, जब पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण धूल और औद्योगिक कचरा मिलता है तब शहर गैस चैंबर बन जाता है।

चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखना ही नहीं चाहता

अनिल जैन

चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे है और आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग सरकार के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी का मददगार बना हुआ है। लेकिन ऐसे सवालों से बेफिक्र चुनाव आयोग ऐसा कुछ भी करता नहीं दिखता जिससे लगे कि वह निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। जब से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान हुआ और 12 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में इसकी शुरुआत हुई है तब से पश्चिम बंगाल में विवाद खत्म ही नहीं हो रहा है। वहां ताजा विवाद बूथ लेवल एजेंट्स बीएलए की नियुक्ति को लेकर छिड़ा है। चुनाव आयोग ने बीएलए की नियुक्ति की शर्तों में थोड़ी ढील दी है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि ऐसा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। गौरतलब है कि अभी तक बीएलए की नियुक्ति के लिए यह शर्त थी कि पार्टियां, जिसे जहां बीएलए बनाएंगी, उसका नाम वहां की मतदाता सूची में होना चाहिए। अब चुनाव आयोग ने इसमें बदलाव करके कहा है कि एक विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति उस पूरे क्षेत्र में कहीं का भी बीएलए नियुक्त हो सकता है। सवाल है कि जब नाम ही बूथ लेवल एजेंट है तो बूथ से बाहर के किसी व्यक्ति को कैसे एजेंट बनाया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास हर बूथ पर एजेंट बनाने के लिए लोग नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग ने यह नियम बदला है।

फिर हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर!

लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ फिर सैन्य कार्रवाई हो सकती है। इस संभावना का कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से आतंकवादियों को अंग्रेजी में चेतावनी दी है। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए विस्फोट के अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की भूटान यात्रा पर गए। वहां उन्होंने इस घटना पर शोक जताया और आतंकवादियों को चेतावनी दी की किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह लाइन अंग्रेजी में बोली। उन्होंने कहा कि, %ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस।' माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस चेतावनी के जरिये दुनिया को भी बता दिया है कि भारत कार्रवाई करेगा। मोदी ने लगभग यही लाइन पहलगाम कांड के बाद बिहार के मधुबनी में बोली थी। उन्होंने वहां एक सभा आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देने की बात करते हुए अंग्रेजी में चेतावनी दी थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। सरकार और सेना की ओर से भी बार-बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वह जारी है। दिल्ली में हुए विस्फोट के तार कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़ने के बाद माना जा रहा है कि सैन्य कार्रवाई होगी। पाकिस्तान को भी इसका अंदाजा है। इसीलिए उसके भी लड़ाकू विमान सीमा के आसपास उड़ान भर रहे है। पाकिस्तान पिछली बार किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार था। इस बार वह ज्यादा तैयारी में रहेगा। भारत को उस हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी। पहलगाम कांड के दो हफ्ते बाद सैन्य कार्रवाई हुई थी। इस बार उससे ज्यादा समय लग सकता है।

उम्मीदवारों की कमाई की जांच होगी

आमतौर पर विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार अपने नामांकन के साथ जो हलफनामा दाखिल करते है, उसके आधार पर मीडिया में उसकी व्याख्या होती है। किसके ऊपर कितने मुकदमे है या किसके पास कितनी संपत्ति है या किसने कहां तक पढ़ाई की है, पांच साल में किसकी उम्र कितनी बढ़ी जैसे मुद्दों में लोगों की दिलचस्पी होती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) नाम की संस्था बहुत व्यवस्थित तरीके से इसका अध्ययन करती है। हर उम्मीदवार का पूरा ब्योरा तीन बार अखबारों में छपता है ताकि लोगों को अपने उम्मीदवार के बारे में हर बात की जानकारी हो। इस बार संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि उम्मीदवारों के हलफनामे पर सरकार और एजेंसियों की भी नजर है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग इस बात की जांच करेगा कि किस उम्मीदवार की संपत्ति ज्यादा बढ़ी है और ज्यादा बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है। गौरतलब है कि कई उम्मीदवारों की संपत्ति पांच साल की अवधि में पांच गुना या दस गुना बढ़ जाती है। जिन उम्मीदवारों का कोई कानूनी रूप से वैध कारोबार है उनकी बात अलग है। लेकिन बहुत से नेता ऐसे है, जिनका कोई कारोबार नहीं है फिर भी संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है। जांच होने पर पता चलेगा कि ऐसा चमत्कार कैसे होता है। एजेंसियों की नजर संभवतः इसलिए भी उम्मीदवारों पर गई है क्योंकि देश के हर चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहरहाल, सवाल है कि नेताओं पर बढ़ते आपराधिक मामलों का क्या होगा?

दिल्ली में साफ हवा के लिए प्रदर्शन

यह शायद पहली बार हुआ कि दिल्ली के लोग साफ हवा के लिए सड़क पर उतरे। पानी के लिए तो प्रदर्शन होते रहे थे। हालांकि साफ पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ है। अभी तो किसी तरह से पानी मिल जाए, इसके लिए प्रदर्शन होते हैं। पहली बार बीती नौ नवंबर को बड़ी संख्या में लोग साफ हवा के लिए प्रदर्शन करने इंडिया गेट पर जमा हुए और उन्होंने वायु प्रदूषण को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पुलिस ने पहुंच कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया और बसों में बैठा कर अलग-अलग जगहों पर ले जाकर छोड़ दिया। ये लोग किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि सिविल सोसायटी के लोग थे। उनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग थे और बच्चे भी थे। इनके हाथ में प्लेकार्ड्स थे, जिन पर लिखा था कि ये लोग सांस लेने के अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरे हैं। सवाल है कि दिल्ली में हर साल वायु प्रदूषण होता लेकिन इस बार क्यों लोग सड़क पर उतरें? इसका जवाब बहुत आसान है। ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि इस बार उनको दिख रहा है कि सरकार प्रदूषण से निपटने के उपाय करने की बजाय आंकड़े छिपाने में लगी है। दिल्ली में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है लेकिन सरकार के हवाले से रोज अखबारों में खबर आ रही है कि दिल्ली में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

वंदे मातरम बनाम जन गण मन

पश्चिम बंगाल हर चुनाव से पहले किसी न किसी तरह से संस्कृति और पहचान की बातें होने लगती हैं। याद ही होगा कि कैसे पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की तरह की दाढ़ी रख ली थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में वे उसी तरह से प्रचार करते रहे। भाजपा ने किसी बहाने ईश्वरचंद विद्यासागर के सम्मान का भी मुद्दा बनाया। हालांकि उसका उसे कोई फायदा नहीं हुआ। ममता बनर्जी बाहरी बनाम बांग्ला का मुद्दा बना कर चुनाव जीत गईं। पिछली बार %जय श्रीराम' बनाम %जय मां काली' का भी मुद्दा बना। यह भी अस्मिता का ही सवाल था। इस बार चुनाव से पहले कुछ समय तक जगन्नाथ धाम का विवाद चला। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे धाम कहने पर विवाद हुआ। अब वंदे मातरम और जन गण मन का विवाद शुरू हो गया है। भाजपा और केंद्र सरकार वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर उत्सव मना रही है। इस सिलसिले में दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उधर भाजपा के एक नेता ने कह दिया कि जन गण मन की रचना इंग्लैंड के राजा के सम्मान में हुई थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात वापस ली। इस बीच अबू आजमी और जिया उर रहमान बर्क जैसे मुस्लिम नेताओं ने वंदे मातरम गाने से इनकार करके विवाद और बढ़ा दिया है। अब ममता को इस विवाद में उलझाने की कोशिश हो रही है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कल्पना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पश्चिमी एन्क्ले., दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/570, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/0882)

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी के निधन पर शोक सभा का हुआ आयोजन

बहराइच।

झांसी में अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार संगठन द्वारा आयोजित स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोकुल प्रसाद बबेले सम्मान यात्रा के पश्चात सायं काल आवास विकास झांसी स्थित संगम विहार कालोनी निवासी वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सत्यदेव तिवारी की अध्यक्षता में बलिया जनपद के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम विचार पाण्डेय के निधन पर शोक श्रद्धांजलि सभा की।

उपस्थित सभी जनों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में उनके द्वारा किए गए योगदान को याद किया। शोक प्रस्ताव पर बोलते हुए अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के प्रदेश कार्यवाहक महामंत्री रमेश कुमार मिश्र ने कहा कि पंडित राम विचार पाण्डेय एक कर्मठ, उत्साही और हमेशा खुशी बांटने वाले देश भक्त थे। देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने वाले वीर योद्धा थे। पाण्डेय जी का स्नेह और आशीर्वाद हमेशा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारी परिवारों को मिलता था। उनके निधन से स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन की अपूर्णनीय क्षति हुई है जो भविष्य में पूरा नहीं किया जा सकता है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी सत्यदेव तिवारी ने राम विचार पाण्डेय के निधन पर उनकी आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस महान दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से कामना की। पश्चात उपस्थित सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के सदस्यों ने दो मिनट मौन धारण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।अन्त सभाध्यक्ष सत्यदेव त्रिपाठी वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी ने उपस्थित सभी सेनानी उत्तराधिकारियों को आशीर्वचन से अभिसिंचित किया। इस अवसर पर बहराइच जनपद से भानु प्रताप द्विवेदी एडवोकेट, बहराइच जिला संगठन के महामंत्री राजू मिश्र उर्फ मुन्ना भैया, झांसी जनपद के अभय तिवारी तथा उनके परिजन उपस्थित रहे।

समाजसेवी मोश अब्दुल्ला को लखनऊ में सम्मानित किए जाने से लोगों ने किया खुशी का इजहार

बहराइच।

एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल (ए एमपी) की नेशनल एन.जी.ओ. कान्फ्रेंस, इस्लामिक सेन्टर ऑफ इंडिया लखनऊ में आयोजित हुई, जिस में देश भर से शिक्षाविद, समाज सुधारक, बुद्धिजीवी सम्मिलित हुए। इस कान्फ्रेंस में अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर जमीरुद्दीन शाह, शाहीन ग्रुप के अध्यक्ष अब्दुलकदीर, जकात फाउन्डेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन डाक्टर सय्यद जफर महमूद, ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रो-वाइस चांसलर ब्रिगेडियर अहमद अली, पूर्व जिला जज बी.डी. नकवी, प्रसिद्ध चिकित्सक डाक्टर कौसर उस्मान, डाक्टर कौनैन कौसर, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक और नेशनल योगा ट्रेनर डाक्टर बदरुलइसलाम समेत पचासों स्पीकर्स और देश भर की सैकड़ों एन.जी.ओज. के हजारों कारकुनान ने शिरकत की। कान्फ्रेंस में अल्पसंख्यक, वक्फ एंव हज राज्य मन्त्री दानिश आज़ाद भी सम्मिलित हुए। दो दिवसीय कान्फ्रेंस में शिक्षा और रोजगार पर विस्तृत चर्चा हुई। इस कान्फ्रेंस में दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी एवार्ड से सम्मानित किया गया। बहराइच के सुप्रसिद्ध समाज सेवी मोहम्मद अब्दुल्लाह भी चेन्जमेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित हुए। मोहम्मद अब्दुल्लाह को सम्मानित किए जाने पर बहराइच वासियों में खुशी का माहौल है। एडवोकेट सुहेल इकबाल, मोहम्मद शफीक, राकेश पाण्डेय, बिन्नू सिंह, डाक्टर अब्दुलवजूद खां, चांद मियां, राजेश जायसवाल, बच्चे भारती, जमाल अहमद, सलीम सिद्दीकी, अरशद अली मेकरानी, शफीक अहमद बाग़बान ने एवार्ड से सम्मानित किए जाने पर मोहम्मद अब्दुल्लाह को मुबारकबाद पेश की है।

जीवन में सामंजस्य स्थापित करते हैं खेलः रामवीर सिंह

विधायक कुन्दरकी ने किया खेल प्रतियोगिता 'जोश' का शुभारम्भ

मुरादाबाद। मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में 12वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता 'जोश' का शुभारम्भ कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने किया। शुभारम्भ के बाद खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई, जिनमें छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, वॉलीबॉल बास्केटबॉल, कैरम, कबड्डी, टेनिस जैसे रोमांचक खेल शामिल रहे, जिनमें विद्यार्थियों ने शानदार कौशल और टीम भावना का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि खेल हमारे जीवन में शिक्षा जितने ही आवश्यक हैं। खेलों के माध्यम से हम जीवन के उतार-चढ़ाव के बीच सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में अनुशासन, निष्ठा और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खेलो इण्डिया और फिट इण्डिया मूवमेंट से युवाओं में नया जोश भरा है। इस अवसर पर चेयरमैन सुभाष चंद्र ढल, कमल चंद्र अग्रवाल, सचिव नीरज विनोद खन्ना, डॉ हरजीत सिंह, नजमुल इस्लाम, शैलेश खन्ना, रोहित ढल, प्रधानाचार्य मोहम्मद अरशद, डॉ टीपी शीवा सहित कॉलेज के अध्यापक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

40वें अखिल भारतीय प्राइजमनी इंदिरा मैराथन प्रयागराज जिलाधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

प्रयागराज।

आगामी 19 नवम्बर को आयोजित होने जा रही 40वीं अखिल भारतीय प्राइजमनी इंदिरा मैराथन को लेकर सोमवार को संगम सभागार में जिलाधिकारी मनीष वर्मा द्वारा विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने मैराथन के इतिहास, तैयारियों, मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था और खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्राइजमनी के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होने वाली यह मैराथन देश की एकमात्र ऐसी प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन लगातार 1985 से प्रतिवर्ष 19 नवम्बर को–पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की जयंती पर–किया जाता रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष मैराथन का 40वां संस्करण विशेष रूप से भव्य और ऐतिहासिक होगा। मैराथन की कुल दूरी 42.195 किमी निर्धारित है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के धावक भाग लेंगे।

मैराथन सुबह 5:30 बजे आनंद भवन से शुरू होगी एवं अपने निर्धारित मार्ग–लाल भवन, लोकसेवा आयोग, तेलियरगंज, सहसों, हाइकोर्ट, स्टैनली रोड, दारागंज, काली सड़क, बसीरगंज, कंधरपुर, झूंसी होकर पुनः उसी मार्ग से वापस लौटते हुए तेलियरगंज से होते हुए आनंद भवन–पर समाप्त होगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि धावकों की सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल सहायता, वाटर पॉइंट, तथा रूट मॉनिटरिंग के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, खेल विभाग तथा नगर निगम सहित कई एजेंसियों को अलग-अलग जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं।

सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि मैराथन के संचालन में कोई त्रुटि न रहे। मेडिकल एम्बुलेंस, प्रथम उपचार केंद्र और वॉलंटियर टीमों को भी तैनात किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि पुरुष तथा महिला दोनों वर्गों में प्रथम पुरस्कार 2,00,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1,00,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 40,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा 11 से 15 स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रत्येक तथा 16 से 20 स्थान पाने वालों को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और प्रतियोगिता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह प्राइज स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय धावकों का इस मैराथन से गहरा जुड़ाव रहा है। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय धावक इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं, जिससे प्रयागराज की इस मैराथन को वैश्विक पहचान मिली है। जिलाधिकारी ने अंत में शहरवासियों से अपील की कि आयोजन के दिन यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने में प्रशासन का सहयोग करें और धावकों का उत्साहवर्धन करें। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की पहचान बन चुकी इंदिरा मैराथन को सफल बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

कुख्यात बदमाशों के खात्मे पर किया एसएसपी का सम्मान

मुरादाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश आसिफ टिड्डा और इलियास उर्फ दीनू के एनकाउंटर से शहर के निर्यातकों, डॉक्टरों और व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। रंगदारी गिरोह के चंगुल से बचे व्यापारी संगठनों ने इसके लिए पुलिस को शुक्रिया कहते हुए एसएसपी सतपाल अंतिल को सम्मानित किया। मुरादाबाद के विभिन्न व्यापारिक संगठनों और सामाजिक संगठनों की ओर से सस्कको सम्मानित करने का सिलसिला पिछले कई दिनों से चला आ रहा है। सोमवार को भी कई संगठनों ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर एसएसपी को इस एनकाउंटर के लिए सम्मानित किया। व्यापारी संगठनों ने कहा कि, मुरादाबाद बिजनेस सिटी है। यहां इस तरह के गैंग के पैर जमा लेने पर व्यापारियों को अपना काम धंधा करना बेहद मुश्किल हो जाता।

छात्रों का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम में चयन

मुरादाबाद।

चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी के छात्रों का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम में कक्षा 6 च 9 के लिए चयन हो गया है। छात्रो को अकादमी के डायरेक्टर केतन गोयल ने पट्टि पहनाकर व शील्ड देकर उ=वल भविष्य की कामना की। छात्रों के माता-पिता ने इस खुशी के अवसर पर सभी शिक्षकों को मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया और कहा कि यह चयन चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी के शिक्षकों द्वारा जो कड़ी मेहनत की गई. उसी का परिणाम है। सैनिक स्कूल का यह एग्जाम कक्षा 6 व 9 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। ऑल इंडिया लेवल पर अपनी जगह बनाने के लिए बड़ा ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अधिकतर माता-पिता का सपना होता है कि उनके ब'चे का प्रवेश ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम में हो जाये। इन छात्रों ने सैनिक स्कूल में चयन पाकर अपने माता-पिता व चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी का नाम देश भर में रोशन किया है। डायरेक्टर केतन गोयल ने बताया कि जो छात्र इस वर्ष कक्षा 4, 5, 6, 7 व 8 में अध्ययनरत हैं वह भी सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम की तैयार नये बैच में प्रवेश लेकर कर सकते हैं। सैनिक स्कूल में चयन की अपार सफलता के बाद 18 जनवरी 2026 में होने वाले इंट्रेंस एग्जाम के लिए दाखिले अभी चल रहे है। आने वाली 2026 की परीक्षा में हमारी कोशिश रहेगी कि 'यादा से 'यादा सेलेक्शन सैनिक स्कूल में हो सके। शिक्षक अमित यादव, आलोक प्रताप, अंकित चौधरी व प्रमोद कुमार के अथक प्रयासों से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम 2025 में तीन विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं। निष्ठा व अनुष्का का चयन कक्षा के लिए तथा अमिश का चयन कक्षा 9 के लिए हुआ है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम जो कि इस बार 18 जनवरी 2028 को होना है, के लिए भी दाखिले अभी चल रहे है। आईएएस, एसएससी के लिए भी नये बैच प्रारम्भ किये गये है। जिन छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है वह सभी जल्दी ही एडमिशन लेकर नये बैच में अपनी तैयार शुरू कर दें क्योंकि अब समय 'यादा नहीं बचा है। इस अवसर पर प्रबन्धक मुकेश कुमार, प्रशासक सूरज देओल, सभी शिक्षक व शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे।

टीएमयू के सीटीएलडी की स्पीचमास्टर में समृद्धि शर्मा अव्वल

मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के सेंटर फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड डवलपमेंट-सीटीएलडी की ओर से आयोजित भाषण प्रतियोगिता- स्पीचमास्टर 3.0 में कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ के बीए-एलएलबी-ऑनर्स की छात्रा समृद्धि शर्मा विजेता रही। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के बीए-बीएड के छात्र अतिंद्र कुमार झा ने द्वितीय और बीएससी-बीएड की छात्रा मान्या शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इससे पूर्व सीटीएलडी के डायरेक्टर प्रो. पंकज कुमार सिंह, आईक्यूएसी के डायरेक्टर डॉ. निशीथ कुमार मिश्रा, वीवो के डीजीएम- एचआर तरुण कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉ. नेहा आनंद आदि ने मां सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलित करके ऑडी में स्पीचमास्टर 3.0 का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में 315 छात्रों में से 36 छात्रों ने फाइनल राउंड में जगह बनाते हुए ऑन-द-स्पॉट स्पीच दी।

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को किया तलब, दिल्ली पुलिस ने जारी किए दो समन

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को दो अलग-अलग मामलों में समन जारी किया है। यह समन फरीदाबाद में आतंकवाद मॉड्यूल मामले और विश्वविद्यालय के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के दो मामलों की चल रही जांच से संबंधित है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। हाल ही में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसते हुए दो प्राथमिकी दर्ज की थी। एक प्राथमिकी चीटिंग की और दूसरी फोर्जरी की दर्ज की। यूजीसी की शिकायत पर दर्ज इन मामलों के बाद पुलिस टीमें ओखला स्थित यूनिवर्सिटी ऑफिस पहुंची और कई दस्तावेज मांगे।

एनएएसी और यूजीसी ने गंभीर अनियमितताएं चिन्हित की है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस भी दिया। उधर, फरीदाबाद की सीआईए के पुलिसकर्मी भी ओखला ट्रस्ट व मालिक के घर पहुंचे और परिजनों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य

कागजात लिए। यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत यूजीसी ने दर्ज कराई है। एफआईआर में यूनिवर्सिटी की मान्यता और दस्तावेजों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो एफआईआर दर्ज करने की पुष्टि करते हुए बताया कि यूजीसी ने शिकायत में कहा है कि यूनिवर्सिटी ने यूजीसी सेक्शन-12 के उल्लंघन पर आधारित है, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटी की कथित फर्जी मान्यता (एक्रिडेशन) दावों से जुड़ी है।

अब तक क्या-क्या हुआ?

- दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम आज ओखला स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची।
- यूनिवर्सिटी को एक औपचारिक नोटिस जारी किया गया।
- पुलिस ने कई दस्तावेज और रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध कराने को कहा।
- यूजीसी और एनएएसी ने अपनी समीक्षा में अनियमितताओं की पुष्टि की।
- दोनों एफआईआर की जांच क्राइम ब्रांच की अलग-अलग टीमें कर रही हैं।

जांच पर इसका क्या असर?

कानूनी जानकारों का कहना है कि दो एफआईआर दर्ज होने से जांच की दिशा बदल सकती है। फॉर्जरी और चीटिंग जैसे आरोप बहुत गंभीर श्रेणी में आते हैं, और अगर दस्तावेजों में अनियमितता मिलती है, तो यह यूनिवर्सिटी के संचालन पर भी प्रभाव डाल सकता है।

विदेशी फंडिंग पर बड़ा खुलासा, यूनिवर्सिटी का इन्कार

दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस और जांच एजेंसियों की फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की हर एक एक्टिविटी पर नजर है। इस बीच अल फलाह को विदेशी फंडिंग मिलने की बात सामने आई है। अब इसकी जांच की जा रही है। हालांकि अल फलाह यूनिवर्सिटी विदेशी फंडिंग से साफ इन्कार कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर मो. रजी ने बताया कि यूनिवर्सिटी की फंडिंग सिर्फ फीस से होती है। उनका कहना है कि जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगे। फरीदाबाद पुलिस ने जमीन के दस्तावेज मांगे थे जो उन्हें दे दिए गए हैं।

पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा

***बांग्लादेश कोर्ट ने छात्रों की हत्याओं का दोषी माना; उम्रकैद की भी सजा**

***फैसला राजनीति से प्रेरित- शेख हसीना**

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ लगे 5 गंभीर आरोपों पर अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व पीएम को दोषी बताते हुए, उन्हें फांसी की सजा दी है। अदालत के इस फैसले से न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में शेख हसीना को मानवता के खिलाफ कदम उठाने का दोषी माना है। कोर्ट ने पूर्व पीएम के अलावा बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जस्टिस मोहम्मद गोलाम मजूमदार की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि तीनों आरोपी प्रदर्शनकारियों की हत्या में शामिल थे, जिसके कारण पूरे देश में हिंसा भड़की थी। कोर्ट ने शेख हसीना और कमाल को भगोड़ा घोषित करते हुए चौधरी अब्दुल्ला को सजा देने की बात कही है।

आजम खान और उनके बेटे अब्दूला को 7-7 साल की सजा

रामपुर।

समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक विशेष सांसद-विधायक मजिस्ट्रेट अदालत ने दोहरे पैन कार्ड मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है। खान और उनके बेटे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता आकाश सक्सेना ने दिसंबर 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में, सक्सेना ने आरोप लगाया कि दोनों के पास अलग-अलग जन्मतिथि वाले दोहरे पैन कार्ड थे। सक्सेना ने आरोप लगाया कि खान और उनके बेटे ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके दो पैन कार्ड प्राप्त किए थे और उनका उपयोग बैंकिंग लेनदेन और आयकर

विवरण के लिए कर रहे थे। दोषसिद्धि के बाद, आजम खान और अब्दुल्ला दोनों को अदालत कक्ष में ही हिरासत में ले लिया गया। जल्द ही सजा सुनाई जाने की उम्मीद है। शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी आदेश सुनाए जाने के समय मौजूद थे। आकाश सक्सेना द्वारा अब्दुल्ला आजम पर अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग करके

2 महीने पहले छूटे थे, अब फिर जेल जाएंगे; फर्जी पैन कार्ड केस में फैसला

दो पैन कार्ड प्राप्त करने का आरोप लगाने के बाद 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, ये पैन कार्ड गलत और जाली दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए थे और कथित तौर पर बैंकिंग, आयकर रिकॉर्ड और चुनावी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। एक पैन कार्ड में अब्दुल्ला की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर, 1990 दर्ज थी।

अखिलेश संभालें कमान... बिहार में महागठबंधन की हार के बाद बैकफुट पर इंडी गठबंधन, विपक्षी नेता ने उठाई आवाज

***कांग्रेस की करारी हार के बाद नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा**

***इससे पहले ममता के नाम की भी हुई थी चर्चा**

***अखिलेश यादव को नेतृत्व सौंपने की उठी मांग**

नई दिल्ली।

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने कहा है कि अखिलेश यादव को विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्यों में से एक, उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। पिछले साल हुए आम चुनाव में 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के बाद लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि अगर बिहार में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते तो महागठबंधन सरकार बना लेता। अखिलेश यादव ने बार-बार बैलेट पेपर से मतदान की वकालत की है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के मद्देनजर ऐसा बयान काफी अहम माना जा रहा है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, जिसने 2020 के बिहार चुनावों में 19 सीटें जीती थीं, इस बार सिर्फ छह सीटें ही जीत पाई। यह तब हुआ जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं ने चुनाव से पहले कई रैलियां कीं।

बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण

19 को भंग होगी विधानसभा, राज्यपाल से मिले सीएम, आज जेडीयू-बीजेपी विधायक दल की बैठक

पटना। जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू) नेता विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को घोषणा की कि बिहार मंत्रिमंडल ने 19 नवंबर से प्रभावी रूप से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की औपचारिक सिफारिश कर दी है। यह निर्णय आज दिन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। यह सिफारिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भेज दी गई है। इससे पहले, नीतीश कुमार ने पटना स्थित राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की शानदार जीत और नई सरकार के संभावित गठन के बाद सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। घटनाक्रम की जानकारी देते हुए चौधरी ने पत्रकारों को बताया आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने 19 नवंबर से

मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की है। यह बात मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को बता दी गई है। कैबिनेट ने दो अतिरिक्त प्रस्ताव भी पारित किए। दूसरे प्रस्ताव में मौजूदा सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार भर के सरकारी अधिकारियों के सहयोग के लिए उनकी सराहना की गई। चौधरी ने कहा कि दूसरा प्रस्ताव यह था कि वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन और क्रियान्वयन किया है। इसके लिए मुख्य सचिव सहित बिहार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की सराहना की गई है। तीसरे प्रस्ताव में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में एनडीए की प्रचंड जीत को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा की गई। जदयू नेता ने आगे कहा, तीसरा प्रस्ताव यह था कि हाल ही में संपन्न आम चुनावों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने जबरदस्त सफलता हासिल की और प्रचंड बहुमत हासिल किया। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और उनके नेतृत्व में एनडीए के सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले आज, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 18 नवंबर को अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार बनाने का काम 21 नवंबर तक पूरा हो जाएगा।

बिहार में पुरानी विधानसभा भंग, नीतीश के नेतृत्व को सलाम; अब नई सरकार का इंतजार

जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, उसी राज्य ने दिया कानून-व्यवस्था का मॉडल- सीएम योगी

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले और आज के उत्तर प्रदेश की तुलना करते हुए कहा कि जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, बहन-बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, आज उसी प्रदेश ने देश को कानून-व्यवस्था का मॉडल दे दिया है। यह प्रयास से ही हो सकता है। आज हर त्योहार उमंग और उत्साह से मनाया जा रहा है। चाहे होली-दीवाली हो या ईद-बकरीद या फिर क्रिसमस। कानून का शासन ऐसे ही होता है। बीबीडी विश्वविद्यालय में सोमवार को मेधावियों को पदक और उपाधि प्रदान करने के बाद योगी ने कहा कि दवा कड़वी तो लगती है, लेकिन परिणाम सुखद होता है। कानून-व्यवस्था के कारण ही आज प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। आठ वर्ष पहले इसी

प्रदेश में पांच वर्षों में पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश भी नहीं मिलता था। उत्तर प्रदेश का देश की अर्थव्यवस्था में केवल आठ प्रतिशत का ही योगदान था। आज ईज ऑफ डूइंग में 14वें नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश की लगभग सभी योजनाओं में प्रदेश अंतिम पांच पायदान में रहता था। आज शीर्ष तीन स्थान में रहता है। सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर में उत्तर प्रदेश के योगदान की भी प्रशंसा की। कहा, यहां के बने ड्रोन ने भी बड़ी भूमिका निभाई। जब ब्रह्मोस यूनिट की स्थापना की बात आई तब भूमि की चुनौती सबसे बड़ी थी, लेकिन हमने तय किया की राजधानी में ही ब्रह्मोस के लिए मुफ्त में जगह देंगे। हमसे कहा गया कि इतनी बड़ी जमीन मुफ्त में कैसे दी जा सकती है, लेकिन मैंने तय कर लिया था। उस जमीन की उस वक्त बमुश्किल कीमत 200 करोड़ रही होगी, लेकिन ब्रह्मोस यूनिट स्थापित होने से उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष 300 से 500 करोड़ रुपये जीएसटी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा सेंटर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हब के रूप में स्थापित है, लेकिन इस दिशा में संस्थानों को और काम करना होगा। तीन, छह महीने और एक वर्ष के कोर्स एआइ, ड्रोन टेक्नोलॉजी व रोबोटिक विषय में शुरू किए जाने चाहिए, ताकि युवा इस क्षेत्र में आगे जा सकें।

जम्मू को सुरक्षित बनाने चले थे मगर दिल्ली को असुरक्षित बना दिया, महबूबा मुफ्ती ने मोदी और शाह पर कसा तंज

श्रीनगर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लाल किले के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के बाद केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने जम्मू-कश्मीर में ''झूठी सामान्य स्थिति'' का दिखावा किया है, जबकि देश में कट्टरपंथ और असुरक्षा बढ़ रही है। उन्होंने कहा, ''आप दुनिया को बताते रहे कि कश्मीर शांत है, लेकिन कश्मीर की गूंज सीधे लाल किले तक पहुंच गई। महबूबा ने कहा कि आप जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा करते थे, लेकिन आपकी नीतियों ने दिल्ली को भी असुरक्षित कर दिया। पीडीपी ने दिल्ली और नौगाम में हुए दोनों विस्फोटों की पारदर्शी जांच की मांग करते हुए यह भी दावा किया कि ''कश्मीर और शेष भारत के बीच संवाद समाप्त हो चुका है''। हम आपको बता दें कि महबूबा का यह बयान ऐसे समय आया है जब एनआईए ने 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर कार-बम धमाके की जांच तेज कर दी है। एनआईए ने रविवार को आमिर रशीद अली को गिरफ्तार किया, जो आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ साजिश रचने का आरोपित है। हमले में इस्तेमाल कार आमिर रशीद अली के नाम पर ही दर्ज थी।

टिप्पणी करने से पहले अपना घर संभालें मोदी : गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया टिप्पणी की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि मोदी को ऐसी ''टिप्पणी करने से पहले अपना घर संभालना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे एवं राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में कहा था, ''मुझे लगता है कि आगे कांग्रेस में एक और बड़ा विभाजन हो सकता है। इस पर पलटवार करते हुए गहलोत ने एक्स पर लिखा,

''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस पार्टी में टूट का सपना देख रहे हैं एवं इस संबंध में जो टिप्पणियां कर रहे हैं वे एकदम बकवास हैं। उन्होंने कहा, ''मोदी जी को कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने से पहले अपना घर संभालना चाहिए। आज लगभग दो साल बीतने के बाद भी भाजपा में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जा सका है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के बीच फूट पड़ी हुई है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेता राजग सरकार द्वारा देश के सामने पैदा की गई चुनौतियों से पार पाने में सक्षम हैं।

ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, आर्मी चीफ की पाकिस्तान को खुली चेतावनी; दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद सेना है तैयार

नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार धमाके के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान और उसके सहारे चल रहे आतंकी संगठनों को बहुत बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की हाल की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर थी और देश हर बड़ी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना प्रमुख ने सोमवार को चाणक्य डिफेंस डायलॉग में कहा कि भारत आतंकियों और उन्हें समर्थन देने

वालों से एक ही तरह से निपटेगा। उन्होंने कहा, जब कोई देश राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो यह भारत की प्रगति में बाधा बनता है। ऐसे में कार्रवाई करना हमारी मजबूरी होती है। जनरल द्विवेदी ने दोहराया कि भारत का रुख साफ है टॉक्स और टेरर साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है लेकिन जो देश या संगठन आतंक को बढ़ावा देंगे उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा। सेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे में पूरा हुआ और इससे भारत की क्षमता साफ दिखती है।

उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान फिर मौका देगा तो हम उसे सिखाएंगे कि पड़ोसी देशों के साथ जिम्मेदारी से कैसे व्यवहार किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज की लड़ाइयां मल्टी-डोमेन होती हैं और लंबे समय तक चल सकती हैं, इसलिए सेना हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहती है।

उमराह के लिए गए 45 भारतीयों की मौत

नई दिल्ली।

सऊदी अरब में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई है। मरने वालों में अधिकतर हैदराबाद के निवासी थे। यह हादसा उस समय हुआ, जब उमराह के लिए गए लोगों को लेकर जा रही बस एक तेल के टैंकर से टकरा गई। सऊदी अरब के मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसा मदीना के नजदीक हुआ और हादसे में मरने वाले भारतीय उमराह यात्री है। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त ने इसकी पुष्टि की है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट्स के अनुसार, उमराह पर लोगों को लेकर बस मक्का से मदीना जा रही थी, जब वह रास्ते में डीजल टैंकर से टकरा गई। हादसा स्थानीय समय अनुसार, सुबह करीब 1.30 बजे मुहरास या मुफरिआत इलाके में हुआ, जो मदीना के करीब है। हादसे के समय कई यात्री सो रहे थे। टक्कर लगते ही बस आग की लपटों में घिर गई और लोगों को बचने

का भी समय नहीं मिला। हादसा इतना भयानक था कि मृतकों की पहचान करना भी मुश्किल है। हादसे में 45 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

हैदराबाद पुलिस आयुक्त ने की 45 मौतों की पुष्टि हैदराबाद पुलिस आयुक्त ने बताया है कि सऊदी अरब में हुए बस हादसे में 45 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों में अधिकतर हैदराबाद के निवासी हैं।

मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने बताया कि बीती 9 नवंबर को हैदराबाद से 54 लोग उमराह के लिए जेद्दाह गए थे और इन लोगों को 23 नवंबर को वापस आना था। इन 54 में से चार लोग एक कार से मक्का से मदीना जा रहे थे और चार अन्य लोग मक्का में ही रुक गए थे। बाकी लोग हादसे का शिकार हुई बस में सफर कर रहे थे।

हादसे के समय बस में 46 लोग सवार थे। हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि हमें जो सूचना मिली है, उसके मुताबिक 45 लोग मारे गए हैं और ये लोग 23 नवंबर को हैदराबाद लौटने वाले थे। एआईएमआईएम विधायक माजिद हुसैन ने भी बताया कि हमें जो शुरुआती रिपोर्ट मिल रही है, उसके तहत हादसे में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हम पीड़ित परिवारों से संपर्क कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से हादसे में मारे गए लोगों के शवों को वापस भारत लाने में मदद की अपील की है।

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शवों को भारत लाने की अपील की

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में भारतीय उमरा यात्रियों की बस दुर्घटना पर दुख जताया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से फोन पर बातचीत में ओवैसी ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद की दो ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों की जानकारी रियाद स्थित भारतीय दूतावास के साथ साझा की है। उन्होंने रियाद में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू मैथन जॉर्ज से भी बात की। जॉर्ज ने उन्हें बताया कि स्थानीय अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही अपडेट दिया जाएगा। ओवैसी ने कहा- मैं केंद्र सरकार से, खासकर विदेश मंत्री जयशंकर से अपील करता हूं कि शवों को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और घायलों को जरूरी चिकित्सा मुहैया कराई जाए।